As far as coal and rail are concerned .....

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: One Minute. You said that 5 million tonnes of coking coal is lying at the washeries. I wanted to know why this stock is lying there, why it is not being moved. I did not ask about the delay or commissioning of the plant or about other washeries. That has nothing to do with that.

SHRI VASANT SATHE : The coking coal which has been taken out, which has to be supplied, has to be first washed. It is because the washeries have not come up that the stocks have increased. Otherwise, the stocks would have been disposed of. Between railways and us there is coordination, we are having regular meetings of our officials and today we have no problems with the railways.

श्री अश्विनी कुमार : माननीय सभापति महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि कोल इंडिया या सी० सी० एल० में कोयला देने में कोई भ्रष्टाचार नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उनके ध्यान में ऐसे केसेज आये हैं कि जिनको एक हजार, के हजार या पांच हजार टन मिलता है, जब तक वे एजेंट के माध्यम से नहीं आते हैं और किसी एक खास एजेंट के माध्यम से नहीं आते हैं, वहां के सेल्स आफिसर्स वे-ब्रिज हैं, वह कोयला देते ही नहीं हैं। इसलिये एजेण्ट्स की ऋाप बढ़ी है जिनकी कि वहां अधिकारियों से साठगांठ है और जब एजेण्ट आते हैं, तभी कोयले की डिलीवरी होती है, रियल पार्टीज को नहीं होती है। ऐसी कुछ कम्प्लेंट्स मंत्री महोदय को आई हैं और उनको दूर करने के लिये मन्त्री महोदय कोल इंडिया और सी० सी०एल० के अधिकारियों को किस प्रकार से ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं?

श्री बंसत साठे : अध्यक्ष महोदय, ऐसी तो कोई कम्प्लेंट्स हमारे पास आई नहीं है। मैंने जैसे शुरू में कहा कि हजारों एजेंट्स देश में काम कर रहे हैं उस एरिया में जो विभिन्न राज्यों के उनके मातहत कोयला लेने के लिए स्पोंसर होते हैं। तो एजेंट्स ही आते हैं और वही ड्राफ्टस लेकर आते हैं और उसके बिना कोयला किसी को नहीं दे सकते हैं। इसलिये जहां तक कोल इंडिया का सवाल है हमारे पास इस तरह का कोई शिकायत नहीं है। मैं यह दावा नहीं कर सकता कि ऐसी कोई सांठ-गांठ की बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसी शिकायत आयेगी तो उस पर जरूर कार्यवाही करेंगे।

SHRI JASWANT SINGH: Mr. Chairman, we are discussing one aspect of the problem of the CCL or Coal India which is pithead accumulation. There are other aspects like distribution difficulties production difficulties. The hon. Minister in a signed article in a leading daily today has recommended under his own name that all these difficulties arise primarily from the theory of a public sector. Would, therefore the hon. Minister stand by his conviction and recommend denationalisation of Coal India...?

MR. CHAIRMAN: Not relevant Next question.

अनौपचारिक सलाहकार समितियां

*244. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में अनौपचारिक सलाहकार समितियों के विफल रहने के क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार मंडल में अनौपचारिक सलाहकार समिति की कितनी बैठकें हुई और ऐसी प्रत्येक बैठक में इस समिति में कार्यरत कितने सांसद सदस्य उपस्थित हुए;

(ग) क्या यह सच है कि विभाग बैठकों की तारीख निश्चित नहीं करता और उनके लिये समय पर सूचनायें भी नहीं भेजता; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इन समितियों को सक्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) डाक और दूर संचार विभाग के सर्किल अध्यक्षों के साथ संसद सदस्यों की अनौपचारिक बैठकें कुल मिलाकर नियमित रूप से आयोजित की जाती रही हैं तथा इन बैठकों के न होने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है(**नीचे देखिये**)।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

बिहार डाक और दूरसंचार सर्किलों में अनौपचारिक बैठकों का ब्यौरा

वर्ष	बैठक की तारीख	नोटिस की अवधि	उपस्थित संसद् सदस्यों की संख्या
महाप्रबंधक दूरसंचार और पोस्टमास्टर जनरलों के साथ संयुक्त बैठकें :			
1984 . .	15-9-84	15 दिन	6
1985 . .	11-7-86	54 दिन	8
पूर्ववर्ती डाक तार विभाग का विभाजन होने के बाद पोस्टमास्टर जनरल, बिहार सर्किल के साथ हुई बैठकें।			
1986 . .	17-1-86	57 दिन	7
	11-7-86	52 दिन	5
पूर्ववर्ती डाक तार विभाग के विभाजन के बाद महाप्रबंधक दूरसंचार, बिहार सर्किल के साथ हुई बैठकें।			
1986 . .	17-1-86	57 दिन	7
	11-7-86	43 दिन	5

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : माननीय सभापति जी, तीन वर्ष में इसकी चार बैठकें हुई हैं और 76 में से कभी 5, कभी 6 और कभी 7 सदस्य उपस्थित हुये हैं, उस पर भी माननीय मंत्री जी को यह असफल नहीं लगता। मैंने इस सवाल को इसलिये पूछा कि बिहार में दूरभाष केन्द्र कितने खुले, अगर आप देख लें तो लेगा कि लाइन का विस्तार नहीं हुआ। 7वीं पंचवर्षीय योजना में दूरभाष केन्द्रों की क्या स्थिति है, देख लें तो पता लगेगा कि कुछ काम नहीं हो रहा है। इसी तरह सैटेलाइट स्टेशन खोलने का है उसका भी कोई पता नहीं है ? मल्टी एसेस रूरल रेडियो स्कीम पर कितने सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र खुले हैं, एक भी नहीं। इस प्रकार मैं दर्जनों बातें जानता हूं, लिखता भी रहता हूं और इस समिति में कोई भी काम नहीं होता है। न समय पर सदस्यों को बुलाया जाता है और न ही समय पर इसकी बैठकें होती हैं। मैंने तो सवाल इसलिये उठाया है कि माननीय मंत्री जो अपने जमाने में 76 सांसदों की इस समिति को कारगर बनाएं, हिन्दुस्तान में जो भी हो लेकिन बिहार में इतना पिछड़ापन है कि उसका दो-तिहाई जिला में मैनुअल दूर भाष केन्द्र होने के कारण एस०टी०डी० की सुविधा नहीं है। ...(*व्यवधान*)...

MR. CHAIRMAN: If you want an answer, you must sit down; otherwise the Question hour will be over.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, from the statement that I have already laid on the Table of the House, it is apparent that in 1986 two meetings have been held and more will be held because this year is still going on. Sir, if you see from the statement the number of M.Ps. who attended these meetings was 7 on one occasion and 5 on another. The hon. Member himself has stated that there are 76 M.Ps. from Bihar. Sir, if this is the number who attend and take interest in the meetings, how can it be really effective? Sir, we have another forum—the

Consultative Committee of my Ministry. Then there is another forum—the Telephone Advisory Committee, the Postal Advisory Committee—where M.Ps. are represented.... (*Interruptions*) Sir, dissolving really the Consultative Committee is not the proper way.

MR. CHAIRMAN: You are not supposed to hear the interruptions. You are supposed to answer the question.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, we think the present system of consultation with Members of Parliament by way of Consultative Committee, by way of this Informal Committee, by way of Telephone Advisory Committee and Postal Advisory Committee at the Circle level is sufficient and the only way to activise it is for the hon. Members to take more interest and attend them.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Pending applications for grant of Trade Marks

*245. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the number of applications for grant of trade marks pending till date; and which of the Trade Marks Registry Offices have the highest number of pending applications, indicating the number of applications pending with it;

(b) what is the number of applications pending with each of the Trade Marks Registry Office for more than two, three and four years and what are the reasons for their non-clearance; and

(c) what measures have been taken by Government for expeditious processing and finalisation of the applications and for clearance of the backlog?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) The total number of applications pending examination as on 30-6-1986 is 40862 All the applications filed at the Branch Offices are processed and examined centrally at the Head Office in Bombay. As examination is centralised, the question of pendency individual branch offices does not arise.

(b) The number of applications pending for more than two years but less than three years are 8456. The main reason for the backlog is the tremendous increase in the number of filing of applications.

(c) Every effort is made to speed up the examination of the Applications.

Dereservation in the small-scale sector

*246. SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI N. E. BALARAM:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission is considering a proposal for a selective de-reservation in the small-scale sector; and

(b) if so, what are the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) Reservation/de-reservation of items for manufacture in the small scale sector is a continuing process. The subject is dealt with in the Ministry of Industry. Government of India has appointed an Advisory Committee on Reservation under the Industries (Development and Regulation) Act to make